

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6883/2002

रूप नारायण पुत्र श्री राम पाल, आयु लगभग वर्ष, निवासी गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:

1/1. ज्ञानाराम मीना पुत्र रूप नारायण

1/2. कल्याण मीना पुत्र रूप नारायण

1/3. सोहन लाल मीना पुत्र रूप नारायण

सभी निवासी गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

---वादी/याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।

2. राजस्व अपीलीय प्राधिकरण, जयपुर।

3. सहायक कलेक्टर, जयपुर।

4. ज्ञाना पुत्र स्वर्गीय श्री चंदा (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:

4/1 श्रीमती चंदी पत्नी जैनायण मीना पुत्री ज्ञाना, निवासी गाँव सुरोली धनी देहला, पोस्ट डटेली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4/2 श्रीमती हीरा (मृत)

4/2/1 प्रकाश मीना निवासी गाँव सुरोली, धनी देहला, पोस्ट डटेली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. मंगला पुत्र चंदा (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:

5/1 श्रीमती मूली पत्नी स्वर्गीय श्री मंगला

5/2 राम स्वरूप पुत्र स्वर्गीय श्री मंगला

5/3 रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय श्री मंगला

सभी निवासी सवाई गटोरे, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

6. घिस्या पुत्र भौरिया (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:

6/1 श्रीमती रामप्यारी, पत्नी

6/2 झूंगो, पुत्र

निवासी सवाई गटोरे, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

7. प्रताप पुत्र ग्यारसा (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:

7/1. श्रीमती कानी पत्नी स्वर्गीय श्री प्रताप, निवासी चक गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

8. महादेव पुत्र ग्यारसा (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:

8/1 मास्ट. गोपी विधवा स्वर्गीय श्री महादेव

8/2 जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री महादेव

8/3 हरि नारायण पुत्र स्वर्गीय श्री महादेव

9. राम दयाल पुत्र भुवाना (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:
 - 9/1. देवी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री राम दयाल
 - 9/2. राजू पुत्र स्वर्गीय श्री राम दयाल
 - 9/3. रामू पुत्र स्वर्गीय श्री राम दयाल
 - 9/4. प्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री राम दयाल
 - 9/5. मक्खन पुत्र स्वर्गीय श्री राम दयाल
 - 9/6. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम दयाल, सभी निवासी चक गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. छोट्या पुत्र बिरदा (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:
 - 10/1 श्रीमती मंगली पत्नी स्वर्गीय श्री छोट्या
 - 10/2 रामप्रताप पुत्र स्वर्गीय श्री छोट्या
 - 10/3 मांगी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री छोट्या
 - 10/4 रामकरण पुत्र स्वर्गीय श्री छोट्या
निवासी गाँव नगराला, एनआरआई कॉलोनी के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर।
11. रामू पुत्र बिरदा
12. लाल पुत्र बिरदा (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:
 - 12/1 गिरिराज पुत्र स्वर्गीय श्री लाल, निवासी गाँव नगराला, एनआरआई कॉलोनी के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर।
13. रामधन पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:
 - 13/1 मास्ट. रुक्मा विधवा स्वर्गीय श्री रामधन (हटाया गया)
14. सीताराम पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:
 - 14/1 श्रीमती गोपी पत्नी श्री सीताराम
 - 14/2 कमली पुत्री श्री सीताराम
 - 14/3 रामावतार पुत्र श्री सीताराम
 - 14/4 छोदू पुत्र श्री सीताराम
15. जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:
 - 15/1- शंकर पुत्र जगदीश
 - 15/2- पप्पू पुत्र जगदीश
16. मंगला पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल
17. राम सहाय पुत्र श्री गोपाल
18. गंगा सहाय पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल
19. राजू पुत्र स्वर्गीय श्री ओंकार पौत्र स्वर्गीय श्री गोपाल
20. राकेश पुत्र स्वर्गीय श्री ओंकार पौत्र स्वर्गीय श्री गोपाल
21. श्रीमती छोटी पत्नी स्वर्गीय श्री ओंकार (हटाया गया)
22. गंगा राम पुत्र नानग (मृत) अब इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है:
 - 22/1 श्रीमती रुक्मा, पत्नी
 - 22/2 रामजी लाल, पुत्र
 - 22/3 रामपाल, पुत्र

22/4 रामकिशन उर्फ किशन, पुत्र

22/5 रामस्वरूप, पुत्र

22/6 श्रीमती कैलाशी पत्नी स्वर्गीय बाबू (मृत-पूर्व पुत्र)

22/7 सूरज उर्फ सूरज प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बाबू

सभी निवासी ए-11, सरस्वती नगर, नल्या की ढाणी, सवाई गटोरे, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

23. जय नारायण पुत्र घिस्या

24. तुलस्या पुत्र घिस्या

सभी निवासी गाँव सवाई गटोरे, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

---प्रतिवादी/उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री एन.के. मालू-वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री
अजीत मालू के साथ।

प्रतिवादी के लिए:

श्री एस.एन. मीना

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश

13/03/2024

रिपोर्ट करने योग्य

1. याचिकाकर्ता द्वारा सहायक कलेक्टर, जयपुर (जिसे इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" कहा जाएगा) के न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-उत्तरदाताओं के खिलाफ घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया गया था, लेकिन उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों में से एक यानी प्रतिवादी नंबर 12 मास्ट. सोनी का वर्ष 1981 में निधन हो गया। इसलिए इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने 25.06.1983 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह इंगित किया गया कि नोटिस की तामील के बाद, न तो प्रतिवादी नंबर 12 उपस्थित हुई और न ही कोई लिखित बयान दायर किया गया। आवेदन में यह भी कहा गया था कि उसके कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में, वाद के कारण शीर्षक की सरणी से प्रतिवादी नंबर 12-मास्ट. सोनी का नाम हटाने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए उपरोक्त आवेदन का निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा 23.12.1983 को किया गया था और

यह तथ्य दर्ज किया गया था कि मास्ट. सोनी का निधन हो गया था और यह तथ्य याचिकाकर्ता के संज्ञान में 21.8.1982 को आया था, जबकि उसके द्वारा आवेदन 25.06.1983 को प्रस्तुत किया गया था और विद्वान ट्रायल कोर्ट की राय थी कि आवेदन समय की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था, इसलिए वाद को 23.12.1983 के आक्षेपित आदेश द्वारा समाप्त माना गया।

2. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने राजस्व अपीलीय प्राधिकरण (संक्षेप में, 'आरएए') के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, हालांकि, इसे 12.10.1995 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने राजस्व मंडल (संक्षेप में, "मंडल") के समक्ष दूसरी अपील दायर करके उपरोक्त आदेश को सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी, लेकिन इसे भी 28.07.2000 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। निचली अदालतों द्वारा पारित तीनों निर्णयों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका को दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 23.12.1983 का आदेश स्वयं अवैध है और यह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है क्योंकि प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु के बाद, पूरे वाद को समाप्त नहीं माना जा सकता है क्योंकि अन्य प्रतिवादी रिकॉर्ड पर थे और मुकदमा करने का अधिकार जीवित था। वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 12 ने सम्मन की तामील के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं की और उसने कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इन परिस्थितियों में, वाद को उसकी सीमा तक समाप्त नहीं माना जा सकता था या उसके कानूनी प्रतिनिधियों (संक्षेप में, "एलआर") के प्रतिस्थापन के लिए अनुमति दी जा सकती थी। वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि उक्त प्रतिवादी निस्संतान (issueless) मर गई और उसके कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए वाद के कारण शीर्षक की सरणी से उसका नाम हटाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रावधानों से परे जाकर, पूरे वाद को समाप्त माना गया है और इसे खारिज कर दिया गया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त

प्रस्तुतीकरणों के मद्देनजर, निचली अदालतों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं और उन्हें रद्द और अलग करने योग्य हैं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा **गिरधारी लाल और अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जो 1988(1) आरएलआर 324 में रिपोर्ट किया गया है।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 12 मास्ट. सोनी की मृत्यु के संबंध में तथ्य याचिकाकर्ता के संज्ञान में अच्छी तरह से था, लेकिन उसके द्वारा परिसीमा की वैधानिक अवधि के भीतर प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था और काफी समय बीतने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा समय-वर्जित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन देरी की माफी के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किए बिना। वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, निचली अदालत ने वाद को समाप्त मानने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. बार में दिए गए प्रस्तुतीकरणों को सुना और उन पर विचार किया गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. यह तथ्य विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा 15 प्रतिवादियों के खिलाफ घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया गया था, जिनमें से प्रतिवादी नंबर 12-मास्ट. सोनी ने सम्मन की तामील के बावजूद ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुई और उसने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया और इस बीच, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 25.06.1983 को वाद के कारण शीर्षक की सरणी से उसका नाम हटाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विद्वान ट्रायल जज ने 23.12.1983 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस निष्कर्ष को दर्ज करके पूरे वाद को खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था और प्रश्न में आवेदन परिसीमा की अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था।

7. विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वाद के लंबित रहने के दौरान कुछ प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन न होने पर, पूरा वाद समाप्त हो जाएगा या यह केवल विशेष मृत प्रतिवादी के संबंध में ऐसा होगा। इस प्रश्न का उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम दीवान चंद आनंद और अन्य के मामले में वादी के पक्ष में दिया गया है, जो 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 855 में रिपोर्ट किया गया है और पैरा 31.1 से 31.3 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

“(31.1) एक वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद समाप्त नहीं होगा यदि मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है;

(31.2) यदि एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं, और उनमें से कोई मर जाता है, और जहां मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादियों को, या केवल जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ जीवित रहता है, तो न्यायालय रिकॉर्ड पर उस आशय की प्रविष्टि करने का कारण बनेगा, और वाद जीवित वादी या वादियों के कहने पर, या जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ चलेगा (आदेश 22 नियम 2);

(31.3) जहां दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ जीवित नहीं रहता है, या एक मात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी मर जाता है और मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है, तो न्यायालय, उस संबंध में किए गए एक आवेदन पर, मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाने का कारण बनेगा और वाद के साथ आगे बढ़ेगा। जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर आदेश 22 नियम 4 के उप-नियम 1 के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो वाद मृतक प्रतिवादी के खिलाफ समाप्त हो जाएगा;

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिरावरपु अप्पा राव और अन्य बनाम डोकाला अप्पा राव के मामले में उसी दृष्टिकोण का पालन किया गया है, जो 2022 लाइव लॉ (एससी) 845 में रिपोर्ट किया गया है।

9. इस न्यायालय की राय में, जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु पर पूरे वाद को समाप्त नहीं माना जा सकता है।

10. इस याचिका में दूसरा मुद्दा यह है कि क्या वादी द्वारा दायर किया गया वाद, उन प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है जो एकतरफा रहे और याचिका का लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया?

11. इस मामले में प्रतिवादी नंबर 12 मास्ट. सोनी ने उसे नोटिस की तामील के बावजूद ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने का विकल्प चुना और उसने कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए वह एकतरफा रही और इस बीच उसकी मृत्यु हो गई। जब याचिकाकर्ता ने वाद के कारण शीर्षक से उसका नाम हटाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, तो ट्रायल कोर्ट ने पूरे वाद को समाप्त मानते हुए खारिज कर दिया।

जब मृत प्रतिवादी नंबर 12 मास्ट. सोनी वाद का मुकाबला करने या लिखित बयान दायर करने के लिए पेश नहीं हुई थी, तो उसकी मृत्यु के बाद पूरे वाद को समाप्त के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसे प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन सीपीसी के नियम 4 के उप-नियम (4) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर ट्रायल कोर्ट द्वारा वैध रूप से माफ किया जा सकता था जो निम्नानुसार पढ़ता है:

“4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया - (1) - (3) -

*

*

*

*

(4) न्यायालय जब भी उचित समझे, किसी भी ऐसे प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से वादी को छूट दे सकता है, जिसने लिखित बयान दायर करने में विफल रहा है या

जिसने इसे दायर करने के बाद, सुनवाई में पेश होने और वाद का मुकाबला करने में विफल रहा है; और निर्णय, ऐसे मामले में, उक्त प्रतिवादी के खिलाफ उसकी मृत्यु के बावजूद सुनाया जा सकता है और इसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि इसे मृत्यु होने से पहले सुनाया गया था।”

12. ट्रायल कोर्ट आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत निहित उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा है। छूट की यह शक्ति ट्रायल कोर्ट के लिए उपलब्ध थी, इसे वाद को समाप्त के रूप में खारिज किए बिना इसका प्रयोग किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था।

13. इस स्तर पर यह न्यायालय आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के संशोधन के इतिहास को संक्षेप में ट्रैक करता है ताकि इसके अंतर्निहित उद्देश्य को उजागर किया जा सके। विधि आयोग ने, यह ध्यान देने के बावजूद कि कई उच्च न्यायालयों ने आदेश 22 के नियम 4 के उप-नियम (4) को शामिल करने के लिए स्थानीय संशोधन किए थे, एक समान समावेश के खिलाफ अपनी सिफारिशों की थीं। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन पर विधि आयोग की 27 वीं रिपोर्ट में, आयोग ने निम्नानुसार उल्लेख किया:

“आदेश XXXI, नियम 4 – छूट

यह प्रश्न कि क्या न्यायालय को एक उचित मामले में प्रतिस्थापन की आवश्यकता के संबंध में छूट देने की शक्ति होनी चाहिए, पर विचार किया गया है। कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा, आदि के उच्च न्यायालयों द्वारा एक प्रतिवादी के संबंध में स्थानीय संशोधन किए गए हैं, जो पेश होने और वाद का मुकाबला करने में विफल रहा है। हालांकि, यह महसूस किया जाता है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इस नियम का उल्लंघन करेगा कि एक व्यक्ति के वारिसों की अनुपस्थिति में मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो मर चुका है। इसलिए इन स्थानीय संशोधनों को नहीं अपनाया गया है”।

14. विधि आयोग की 54 वीं रिपोर्ट में, आयोग द्वारा एक बार फिर मामले को विचार के लिए लिया गया। रिपोर्ट अध्याय 22 में निम्नानुसार उल्लेख करती है:

"आदेश 22, नियम 4 - छूट देने की शक्ति - क्या दी जानी चाहिए

22.2. पहला बिंदु आदेश 22 नियम 4 से संबंधित है, जिसके तहत एक कानूनी प्रतिनिधि का गैर-प्रतिस्थापन वाद के समाप्ति का कारण बनता है। क्या न्यायालय को एक उचित मामले में, कानूनी प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन की आवश्यकता के संबंध में छूट देने की शक्ति होनी चाहिए, इस पर पिछली रिपोर्ट में विचार किया गया था। आयोग ने नोट किया कि कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा, आदि के उच्च न्यायालयों द्वारा एक प्रतिवादी के संबंध में स्थानीय संशोधन किए गए थे, जो पेश होने और वाद का मुकाबला करने में विफल रहा है। हालांकि, इसने महसूस किया कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इस नियम का उल्लंघन करेगा कि एक व्यक्ति के वारिसों की अनुपस्थिति में मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो मर चुका है। इसलिए इन स्थानीय संशोधनों को नहीं अपनाया गया था।

22.3 हमने मामले पर आगे विचार किया। एक चरण में हम आदेश 22, नियम 4 में उप-नियम (4) को निम्नानुसार जोड़ने के लिए इच्छुक थे:

"(4) न्यायालय, जब भी यह उचित समझे, किसी भी ऐसे प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से वादी को छूट दे सकता है जिसके खिलाफ मामले को एकतरफा चलने की अनुमति दी गई है या जो अपना लिखित बयान दायर करने में विफल रहा है या जिसने इसे दायर करने के बाद, सुनवाई में पेश होने और मुकाबला करने में विफल रहा है, और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के खिलाफ उसकी मृत्यु के बावजूद सुनाया जा सकता है, और इसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि इसे मृत्यु होने से पहले सुनाया गया था।"

22.4 हालांकि, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस तरह का कोई भी संशोधन एक मृत व्यक्ति के खिलाफ एक डिक्री पारित करने के बराबर

होगा और सिद्धांत में गलत होगा। इसलिए कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की जाती है”।

15. दिलचस्प बात यह है कि 1973 की 54 वीं विधि आयोग रिपोर्ट के बाद के संशोधन ने, अधिनियम 104 के 1976 की धारा 73(i) के माध्यम से, दीवानी प्रक्रिया संहिता में आदेश XXII नियम 4(4) को पर्याप्त रूप से पेश किया। यह ध्यान देने योग्य है कि मूल विधेयक में, आदेश 22 नियम 4(4) के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था। विधेयक को तब संयुक्त समिति को भेजा गया था और नियम 4(4) के समान एक प्रावधान को शामिल करने के लिए एक सिफारिश की गई थी। संयुक्त समिति ने नोट किया:

“55. खंड 73 (मूल खंड 76) - (i) समिति को विभिन्न गवाहों द्वारा साक्ष्य के दौरान सूचित किया गया था कि मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन में देरी वादों के निपटान में देरी के कारणों में से एक थी। समिति को यह भी सूचित किया गया था कि, एक उपचारात्मक उपाय के रूप में, कलकत्ता, मद्रास, कर्नाटक और उड़ीसा उच्च न्यायालयों ने आदेश XXII के नियम 4 में एक नया उप-नियम डाला था कि एक गैर-मुकाबला करने वाले प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं होगा और मामले में दिया गया निर्णय उतना ही प्रभावी होगा जितना कि यह तब होता जब प्रतिवादी जीवित होता।

समिति की राय है कि मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन में देरी और वादों के निपटान में परिणामी देरी से बचने के लिए, संहिता में ही समान प्रावधान किया जा सकता है। तदनुसार आदेश XXII के नियम 4 में नया उप-नियम 3 ए डाला गया है”।

16. संयुक्त समिति ने तदनुसार संशोधन विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान डाला, जिसे बाद में संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया।

“73 आदेश 22 का संशोधन - पहली अनुसूची में, आदेश XXII में,
- (i) नियम 4 में, उप-नियम

(3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियमों को डाला जाएगा, अर्थात्: -

“(4) न्यायालय जब भी उचित समझे, किसी भी ऐसे प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से वादी को छूट दे सकता है, जिसने लिखित बयान दायर करने में विफल रहा है या जिसने इसे दायर करने के बाद, सुनवाई में पेश होने और वाद का मुकाबला करने में विफल रहा है; और निर्णय, ऐसे मामले में, उक्त प्रतिवादी के खिलाफ सुनाया जा सकता है और इसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि इसे मृत्यु होने से पहले सुनाया गया था।”

17. उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि विधायिका ने गैर-मुकाबला करने वाले प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने के विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ आदेश 22 नियम 4(4) के प्रावधान को शामिल किया। इसके विपरीत किसी भी बाध्यकारी कारण की अनुपस्थिति में निचली अदालतें मृत प्रतिवादी मास्ट. सोनी के कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से वादी को छूट देकर वाद की समाप्ति से बचने के लिए उनमें निहित शक्ति का प्रयोग कर सकती थीं और वास्तव में करना चाहिए था। इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि, मृत मास्ट. सोनी के कानूनी प्रतिनिधियों को लाने में विफलता के परिणामस्वरूप वाद समाप्त हो गया, आदेश 22 नियम 4(4) सीपीसी के तहत निचली अदालतों के लिए भरपूर उपलब्ध छूट की शक्ति के बल पर टिकाऊ नहीं हो सकता है।

18. विद्वान ट्रायल जज ने पूरे वाद को समाप्त मानने में एक त्रुटि की है क्योंकि अन्य प्रतिवादी रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे और मुकदमा करने का अधिकार उनके खिलाफ जीवित था और यहां तक कि इस तथ्य को भी पहले और दूसरे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा अनदेखा किया गया है, और आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं जो स्वयं अवैध हैं और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं।

19. उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और निचली अदालतों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को रद्द और अपास्त किया जाता है और वाद को

उसके मूल नंबर पर बहाल किया जाता है। मामले को सहायक कलेक्टर को उसके गुणों पर और कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है।

20. पक्षों को 05.04.2024 को सहायक कलेक्टर, जयपुर के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है। सहायक कलेक्टर, जयपुर से वाद के मुकदमे में तेजी लाने की उम्मीद की जाती है, इस तथ्य को देखते हुए कि वाद वादी/याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1982 में बहुत पहले दायर किया गया था।

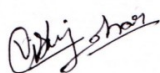
21. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और पक्ष अपने साक्ष्य और तर्क ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

22. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड), जे

आशु/18

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़